

### **Need to increase public funding on healthcare**

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, affordable health care is a distant dream for many people in the country. Every year, healthcare expenses are increasing at a speedy rate. At the same time, the healthcare spending of the Government is only 2.1 per cent of the GDP. This is an alarming situation. In India, the public sector contributes only one-third of the total spending whereas it is 83 per cent in the U.K., 56 per cent in China, 48 per cent in the U.S.A., 46 per cent in Brazil and 39 per cent in Indonesia. After the pandemic attack, we do feel that health is a critical political and policy issue. The emergence of corporate interest in healthcare has further eroded our public health system. This lobby includes pharmaceutical companies, big corporate hospital groups, technical equipment companies, etc. Therefore, there is an urgent need to strengthen our public healthcare infrastructure to ensure widespread access to quality medical services and address the evolving healthcare needs of the nation. The path towards ensuring the right to health for all will be meaningful only if the Central Government guarantees essential primary, secondary and tertiary healthcare services to all citizens. Besides, the Government should ensure the availability of free essential medicines to all people by increasing public spending on drug procurement. The modernization, diversification and expansion of medical institutions largely depends on public funding for healthcare. The increased investment in public health will certainly enhance the overall capacity, infrastructure, and service quality of public health care facilities. I urge the Government to look into it. Thank you, Sir.

### **Demand to decrease the age for contesting Lok Sabha and Assembly Election**

श्री राघव चड्ढा (पंजाब): महोदय, आज आपने मुझे ऐसे मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह मुद्दा राजनीति में युवाओं की भागादारी का है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की औसत उम्र 29 साल है और हमारे संसद की औसत उम्र 54 साल है। कहते हैं कि देश तभी तरक्की करता है जब देश का युवा बुजुर्गों के अनुभव की छाया में रहते हुए देश के विकास के लिए काम करता है। मैं इस संसद का सबसे युवा सदस्य हूँ, लेकिन मैं भी इस देश की औसत आयु से ऊपर हूँ। देश की राजनीति में युवाओं का प्रवेश बहुत मुश्किल है। राजनीति को देश में एक खराब प्रोफेशन की तरह देखा जाता है और यह कहा जाता है कि politics is for the unemployed and unemployable. जहाँ समाज के पिछड़े वर्गों, महिलाओं की संसद में भागीदारी बढ़ाना जरूरी है, वहीं साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि युवा भी राजनीति में आने के लिए प्रेरित हों ताकि अपनी उम्र की बात वह इस महान पटल पर रख पाएं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि देश में चुनाव लड़ने की आयु को 25 साल से कम करके 21 साल करने पर विचार किया जाए, क्योंकि 21 साल की उम्र पर एक युवा अपनी शिक्षा समाप्त

करता है। यदि इस उम्र में युवाओं को राजनीति में आने का प्रोत्साहन मिलेगा, तो वे आगे आएँगे और इस संसद की ऊर्जा को 100 गुना बढ़ाएँगे। नए भारत की नींव रखने के लिए हमें युवा भारतीयों की भागीदारी चाहिए। मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि वह इस तरफ ध्यान दे।

### **Demand for restoration of license of Delhi Milk Scheme**

**श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार):** महोदय, दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) के दूध में कास्टिक सोडा मिलने के बाद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इसका लाइसेंस 13 अक्टूबर, 2023 को निलंबित कर दिया गया, जिसके कारण डीएमएस दूध का उत्पादन और सप्लाई बंद है। डीएमएस दूध की सप्लाई बंद होने से डा. राम मनोहर लोहिया, एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग सहित कई अस्पतालों के मरीजों को कई दिनों तक दूध की आपूर्ति नहीं हुई, मजबूरन कुछ दिनों के उपरांत मरीजों हेतु निजी कंपनियों के दूध की आपूर्ति कराई गई।

इस संयंत्र में खामियों को दूर कर अभी तक लाइसेंस बहाल नहीं किया गया है, जिसके कारण दूध का उत्पादन और आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। कभी डीएमएस दूध हेतु सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी, पर धीरे-धीरे उसकी गुणवत्ता खराब हुई और अंततः अब उसका लाइसेंस निलंबित है। डीएमएस दूध का उत्पादन बंद होने से पहले उसके एक लाख लीटर से अधिक दूध की खपत थी। दूध की सप्लाई बंद होने से आज हजारों डीएमएस बूथ संचालक आर्थिक दबाव में हैं और बूथ से उनकी मजदूरी नहीं निकल पा रही है। यदि बूथ पर दूध की सप्लाई ही नहीं होगी तो कोई भी डीएमएस बूथ पर नहीं आएगा। ऐसे में बूथ संचालकों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः सरकार से मेरी माँग है कि वह डीएमएस के निलंबित लाइसेंस की औपचारिकताएं अविलम्ब पूर्ण कराकर उपभोक्ताओं हेतु डीएमएस का दूध उपलब्ध कराए।

### **Concern over dumping of Fabrics at unfair prices in Indian market**

**SHRI SANJEEV ARORA (Punjab):** Hon. Chairman, Sir, I stand before you today to raise a critical issue gripping the Indian textile industry--the unfair dumping of synthetic knitted fabrics in our market. This practice has created immense pressure on domestic players, jeopardizing jobs, revenue, and the very core of our production capacity.

The polyester industry, currently operating at 70 per cent, faces an unprecedented threat due to unfairly priced imports from China for the past year. Unless immediate action is taken, this threat has the potential to cripple our industry, reducing capacity to less than 50 per cent and causing widespread job and revenue losses.